भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2643

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- तमिलनाडु में डिजिटल कृषि मिशन का कार्यान्वयन

2643. श्री अ. मनिः

श्री नवसकनी के.:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में डिजिटल कृषि मिशन के कार्यान्वयन और किसान पहचान पत्र बनाने, कृषि के रिकॉर्ड को डिजिटल करने और पूरे राज्य में किसानों के लिए डिजिटल सेवाएँ पहुँचाने में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) तमिलनाडु में किसान पहचान पत्र को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, फ़सल की जानकारी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), फ़सल बीमा, ऋण, मृदा स्वास्थ्य और खेती से जुड़ी अन्य सहायक सेवाओं के साथ एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) तमिलनाडु में सार्वजनिक सेवा केंद्रों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि विस्तार तंत्र के माध्यम से डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत किसानों में जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और नामांकन का संवर्धन करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) धर्मापुरी ज़िले में कितने किसान पहचान पत्र बनाए गए हैं और पात्र किसानों के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का धर्मापुरी ज़िले में तकनीक-आधारित परामर्शी सेवाओं, प्रेसीजन खेती, डिजिटल फ़सल निगरानी और खेती की योजनाओं तक बेहतर अभिगम के माध्यम से डिजिटल कृषि सेवाओं को और सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) सरकार, तमिलनाडु सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक, किसान रजिस्ट्री और फसल बुवाई रजिस्ट्री के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करती है। तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में मिशन के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने, प्रगति का आकलन करने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और किसानों के लिए समय पर पहचान पत्र जारी करने, कृषि अभिलेखों के डिजिटलीकरण किसान-केंद्रित डिजिटल सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, प्रभावी और एकसमान कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए, सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने और राज्यों/केंद्र शासित

प्रदेशों को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। साथ ही, राज्य सरकार के अधिकारियों और फील्ड कार्यकर्ताओं के लिए नियमित रूप से क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों को एग्रीस्टैक से जोड़ने, आईटी सिस्टम एकीकरण और किसानों को एग्रीस्टैक-सक्षम सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। 30 जुलाई, 2026 तक, तमिलनाडु में 36.51 लाख से अधिक किसानों को विशिष्ट किसान पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ख) जैसा कि तमिलनाडु द्वारा सूचना दी गई है, एक विश्वसनीय डिजिटल डेटाबेस बनाने के लिए किसान रजिस्ट्री को डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जो पात्र किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के पारदर्शी और कुशल वितरण को सक्षम बनाता है। इस डेटा का उपयोग वर्ष 2025-26 से फसल की जानकारी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), फसल बीमा, ऋण, मृदा स्वास्थ्य और अन्य कृषि सहायता सेवाओं जैसी विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लाभार्थियों के चयन के लिए किया जा रहा है। मिट्टी की उर्वरता की स्थिति को देखने और उपयुक्तता/सिफारिशों के विकल्पों के साथ फसल प्राप्त करने के लिए एक विशेष पोर्टल "तमिल मान वालम" विकसित किया गया है।

(ग) और (घ): धर्मपुरी जिले में कुल 1,63,368 किसान आईडी तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में 4.95 लाख भूमि पार्सल सहित 1.31 करोड़ भूमि पार्सल को किसान आईडी के साथ एकीकृत किया गया है। राज्य सरकार ने तमिलनाडु में डिजिटल कृषि मिशन के तहत जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और किसानों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर किसान रजिस्ट्री के लिए नामांकन केंद्रों में से एक है। कृषि विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर कृषि विस्तार केंद्रों (एईसी) का उपयोग करते हुए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कॉमन रिसॉर्स पर्सन (सीआरपी) और अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारी किसानों के नामांकन को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। आधार प्रमाणीकरण, किसान पहचान पत्र तैयार करने और भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने में किसानों की सहायता के लिए गांवों में विशेष नामांकन शिविर लगाए जा रहे हैं। किसानों और किसान समूहों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के लिए तमिलनाडु में 379 सोशल मीडिया समूह का गठन किया गया है।

(ङ): राज्य सरकार ने राज्यव्यापी डिजिटल कृषि मिशन के कार्यान्वयन के अंतर्गत धर्मपुरी जिले में डिजिटल कृषि सेवाओं को और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। इन पहलों में किसान सहायक और किसान रजिस्ट्री तमिलनाडु एप्लिकेशन के माध्यम से सभी पात्र किसानों के लिए विशिष्ट किसान आईडी बनाकर किसान रजिस्ट्री का विस्तार किया जाना है। रियल टाइम में फसल की निगरानी के लिए जियो-टैग्ड किए गए फील्ड डेटा और एआई-आधारित सत्यापन का उपयोग करके डिजिटल फसल सर्वेक्षण को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। किसानों को उझावर ऐप के माध्यम से फसल प्रबंधन, मौसम, रोग नियंत्रण और पोषक तत्व प्रबंधन पर प्रौद्योगिकी-आधारित

सलाह प्रदान की जा रही है। प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड और आधार-सक्षम सेवा वितरण से किसानों की सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच में सुधार हो रहा है। अब तक 20.32 लाख किसानों ने उझावर ऐप डाउनलोड किया है, जो एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से 24 डिजिटल सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, किसानों द्वारा डिजिटल कृषि सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि विस्तार तंत्र के माध्यम से क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देशभर के किसानों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित एडवाइजरी हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का प्रयोग करते हुए कई डिजिटल सेवाएं जैसे कि भारत विस्तार, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस) तथा किसान सारथी शुरू की हैं। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख एआई पहलें इस प्रकार हैं:

I. भारत विस्तार: कृषि के लिए एक बहुभाषी एआई-संचालित डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है जो किसानों को एक वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और टेलीफोन के माध्यम से रियल टाइम, स्थान-विशिष्ट सलाह, सरकारी योजना की जानकारी, मौसम पूर्वानुमान, मंडी की कीमतें, कीट का पता लगाने और शिकायत सहायता प्रदान करता है। इसके तहत 5.9 लाख से अधिक किसानों की सेवा की गई है और देश भर में 93 लाख+ प्रश्नों का समाधान किया गया है।

II. राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (एनपीएसएस): किसानों को कीट के चित्रों का विश्लेषण करके कीटों के हमलों का पता लगाने में सहायता के लिए एक एआई और मशीन लर्निंग-आधारित प्रणाली विकसित की गई है, जिससे फसल हानि कम करने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सके। यह वर्तमान में देश भर में 73 फसलों और 436 कीटों को कवर करता है।

III. किसान सारथी: आईसीएआर द्वारा एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है और इसका उपयोग कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा किसानों को फसल-विशिष्ट सलाह प्रदान करने के लिए किया जाता है। देश भर में इसके 2.97 करोड़ से अधिक पंजीकृत किसान हैं।

*****